जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

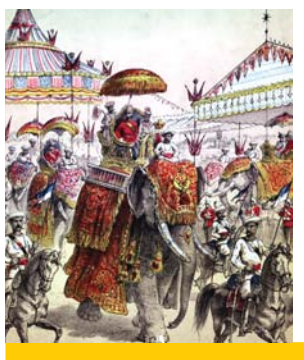

Yodha II Is A Panorama Of Indian Military

During World War II, 2.5 million Indian men were sent to fight and 14 million worked around the clock to keep the war factories and farms running

The Invention of Potato Chips

"Pachaas hazaar kharch ho gaye, par mazaa nahin aaya"

'जब अलावेरु ने सभी निर्णय लिए बिहार में, तो वो हार की जिम्मेवारी भी लें'

अन्ततोगत्वा कांग्रेस ने हार स्वीकार की बिहार में और शुक्रवार को हार का विश्लेषण करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक रखी है दिल्ली में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर। कांग्रेस को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा है कि वह बिहार चुनाव हार गई है। गुरुवार 27 जनवरी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और बिहार कांग्रेस इकाई बैठक करेंगे और बिहार में मिली जबरदस्त पराजय पर मंथन करेंगे। बिहार में कांग्रेस ने 61 में से केवल 6 सीटें जीतीं हैं।

नई दिल्ली से पटना तक सभी हथियार अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यह अपेक्षित है कि वरिष्ठ नेता और नई टीम, जो राहुल गांधी के संरक्षण में आकर पार्टी चला रही है, के बीच करारी भिड़ंत में कोई कसर नहीं रहेगी।

संकट के केन्द्र में कृष्णा अलावेरु हैं, जो एआईसीसी के बिहार प्रभारी थे और जिन्होंने अपनी टीम के साथ सभी फैसले लिए, चाहे कोई भी कुछ कहे।

- बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने चाकू-छुरी तैयार कर रखे हैं, राहुल की युवा टीम की सर्जरी के लिए।
- फ्री व फ्रैंक मंथन करने देने का वादा किया गया है। अतः पूरा घमासान होने की संभावना है, बैठक में।
- अलावेरु का रवैया यह तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि वे अगली पीढ़ी के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, पर, उनके इस तर्क को कोई स्वीकार करता नहीं दिख रहा है।
- एक अन्य ग्रुप यह तर्क दे रहा है कि पार्टी को आरजेडी (तेजस्वी यादव) के चंगुल से मुक्ति लेकर, अपने ही दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने सभी हथकंडे अपनाये थे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए।
- अगर, बैठक में "फ्री व फ्रैंक" बातचीत का मौका नहीं दिया गया तो कांग्रेस का सूरज डूबता सा लग रहा है।

वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अगर अलावेरु और उनकी टीम ने बिना किसी से सलाह-मशवरे के सारे फैसले किए, तो उन्हें नतीजों की पूरी जिम्मेदारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विद्याधर नगर में पैंथर ने बछड़े का शिकार किया

जयपुर, 26 नवम्बर। जंगल में खाना -पीना नहीं मिलने के कारण अब जंगली जानवरों का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में आए दिन नजर आ रहा है। वीवीआईपी इलाके में लैपर्ड के मूवमेंट के बाद, शास्त्री नगर व विद्याधर नगर इलाके में मंगलवार देर रात दो बजे लैपर्ड के होने की सूचना मिली। तुरंत ही यह सूचना पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई और इलाके में दहशत व्याप्त हो गई।

सेक्टर -10 शिव मंदिर के पुजारी सुधांशु ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब दो बजे कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आई। काफी देर तक कुत्तों के भौंकने पर बाहर जाकर देखा तो सब कुछ ठीक लगा। लेकिन बुधवार सुबह मंदिर-परिसर में स्थित बगीचे में एक बछड़ा मरा हुआ मिला। बगीचे में घास के आसपास लैपर्ड के पद- चिन्ह भी दिखाई दिए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरु किया। इसके बाद बुधवार दोपहर पानी पेच इलाके में लैपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया।

- वन विभाग की टीम के प्रयासों के बाद भी पैंथर अभी पकड़ा नहीं गया।

रिहायशी इलाकों में पहले भी लैपर्ड का कई बार मूवमेंट देखा जा चुका है। सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंह पुरा, जगतपुरा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में स्पीकर की पोस्ट पर भाजपा से सीधी टक्कर ली जद (यू) ने

गृह मंत्रालय पद गंवाने के बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए जद (यू) ने यह रणनीति अपनाई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। नव-निर्वाचित बिहार विधानसभा का पहला सत्र, जो 1 दिसम्बर को शुरू होना है, अब गठबंधन पार्टनर, भाजपा और जदयू के बीच एक ताजा टकराव के वातावरण में शुरू होने वाला है, क्योंकि दोनों दल स्पीकर के महत्वपूर्ण पद को लेकर गतिरोध में फंसे हुए हैं।

यह गतिरोध तब और बढ़ गया, जब जदयू ने, अपनी पसंद के रुप में, वरिष्ठ नेता और चार बार के विधायक दामोदर रावत का नाम स्पीकर के लिए प्रस्तावित किया। जदयू का यह कदम भाजपा की पहले की उस घोषणा से सीधे तौर पर टकरा रहा है, जिसमें पार्टी ने अपने अनुभवी दलित नेता और आठ बार के विधायक प्रेम कुमार को स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था।

दोनों पार्टियों के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। बातचीत में शामिल नेता यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह मुद्दा गठबंधन में विश्वास की बढ़ती कमी का द्योतक बन गया है।

- भाजपा ने पार्टी के 8 बार के विधायक एवं अनुभवी दलित नेता प्रेम कुमार का नाम स्पीकर के पद के लिए पहले ही दे दिया था। पर, अब जद (यू) ने अचानक से अपने चार बार के विधायक दामोदर रावत का नाम आगे कर दिया है।
- इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है।
- अब सवाल यह है कि एक दिसंबर से नई विधानसभा का सत्र क्या सत्तारूढ़ गठबंधन, एनडीए की दरारों के साए में होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तनाव सरकार के गठन के शीघ्र बाद तभी शुरु हो गया था, जब गृह मंत्रालय, जिसे नीतीश कुमार ने लगभग दो दशकों तक संभाला था, भाजपा के पास चला गया था। जदयू के नेताओं ने इस कदम को भाजपा के दबदबे एवं प्रभुत्व की अप्रत्याशित पुष्टि के रूप में देखा, जबकि भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि यह पोर्टफोलियो वितरण नई गठबंधन व्यवस्था में "शक्ति समानता" को दर्शाता है।

अब, जब सत्र की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, दोनों दल विधानसभा में टकराव से बचने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। बताया जाता है कि भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेता एक ऐसा फॉर्मूला तलाश रहे हैं, जिससे दोनों की साख बच जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कर्नाटक में नेतृत्व संकट है, सोनिया, राहुल और मैं इसे फिक्स कर देंगे'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में नेतृत्व संकट की बात स्वीकार की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक के नेतृत्व-संकट के जगजाहिर घटनाक्रम को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि राज्य में पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (डीकेएस) के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान का समाधान जल्द हो जाएगा।

पार्टी अध्यक्ष ने आज दोपहर बाद कहा, "सोनिया (गांधी), राहुल (गांधी), और मैं इसे सुलझा लेंगे, सूत्रों ने भी कहा कि 1 दिसंबर, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तक इसका समाधान मिल जाएगा।

सूत्रों ने यह भी कहा कि खड़गे और राहुल गांधी की एक बैठक अगले 48 घंटों में होने की संभावना है, इसके बाद, संभवतः शुक्रवार को सिद्धारमैया और डीकेएस को दिल्ली बुलाया जाएगा।

- सूत्रों ने बताया कि अगले 48 घंटों में खड़गे व राहुल की मीटिंग होगी, फिर मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उन्हें चुनौती दे रहे डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा।
- अब जाकर कांग्रेस ने औपचारिक रूप से माना है कि पार्टी शासित कर्नाटक में नेतृत्व संकट है। पार्टी की सरकार सिर्फ तीन राज्यों में है। इनमें से एक में सरकार पर संकट मंडरा रहा है।
- यह स्वीकारोक्ति एक सप्ताह पहले पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा किए गए इस दावे के विपरीत है कि पार्टी में सब ठीक है।

यह कि कांग्रेस ने अब इस सत्ता संघर्ष को उस राज्य में, जो उन तीन राज्यों में से एक है, जहाँ उसकी सत्ता है, और जहाँ अगले दो साल में चुनाव होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने '26/11' मुंबई आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को बुधवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा।

- उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों व आम नागरिकों के साहस और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा।

गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, मुंबई में 26/11 को हुए दुस्साहसी आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत उनके साहस, बलिदान और शहादत को कभी नहीं भूलेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राबड़ी देवी को सरकारी बँगला खाली करने का नोटिस, आखिर क्यों?

अंदरूनी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने यह कदम भाजपा के दबाव में उठाया है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में भाजपा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाने वाले घटनाक्रम के अन्तर्गत, राज्य के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया है कि वे 10, सर्कुलर रोड वाला बँगला खाली करें। ज्ञातव्य है कि यह बँगला पिछले दस वर्षों से लालू परिवार की विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केन्द्र रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री को अब इस विशाल बँगले के स्थान पर, 39 हार्डिंग रोड पर एक छोटा बँगला आवंटित किया गया है। नई सरकार का अप्रत्यक्ष संदेश साफ है: हालिया चुनाव में राजद की करारी हार के बाद, अब लालू परिवार को इतना बड़ा सरकारी बँगला, जो मुख्यमंत्री के आवास 1अणे मार्ग के ठीक सामने है, रखने का कोई हक नहीं है।

- यह संकेत है कि भाजपा बिहार सरकार में अपना दबदबा कायम करना चाहती है।
- राबड़ी देवी का बँगला, 10 सर्कुलर रोड, गत दस साल से लालू परिवार का केन्द्र है। यह विशाल बँगला मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है।
- सवाल यह है कि नीतीश तो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, फिर बँगला खाली करने का नोटिस अब क्यों दिया गया, वो भी एकाएक, क्या इसके पीछे भाजपा का दबाव है।
- इस नोटिस का आधार पटना हाई कोर्ट के 19 फरवरी 2019 के फैसले को बताया गया है, जो तेजस्वी की याचिका पर आया था, तब तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री का बँगला खाली करने के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बँगला, स्टाफ आदि सुविधाएँ वापस ली जाएं।

पटना हाई कोर्ट के 2019 के फैसले की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो राबड़ी देवी के पास बँगला खाली करने के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं है। हालांकि राजद इस मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है और उसने दृढ़तापूर्वक कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री बँगला खाली नहीं करेंगी। राजद की बिहार इकाई के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एनडीए पर लालू प्रसाद यादव के प्रति मन में द्वेष रखने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने यह कदम "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को खुश करने के लिए" उठाया है। उनकी यह सोच पूरी तरह निराधार भी नहीं लगती, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कभी राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड वाला बँगला खाली कराने की पहल नहीं की। ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न उठता ही है कि यह कदम एकाएक अब क्यों?

देश के अन्य हिस्सों की तरह सरकारी बँगले बिहार में भी राजनीतिक टकराव का प्रतीक रहे हैं। सन् 2015 में जब महागठबंधन सत्ता में आया और तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने, तो वे 5 देशरत्न मार्ग के आलीशान रूप से नवीनीकृत बँगले में रहने लगे और उसे उपमुख्यमंत्री का स्थायी आवास घोषित करवाया। लेकिन 2017 के बाद, जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, तो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विस्फोट के आरोपी उमर को पनाह देने वाला गिरफ्तार

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजधानी में लाल किला के पास हुए कार विस्फोट की वारदात को अंजाम देने वाले आतंकवादी उमर उन नबी को पनाह देने के आरोप में हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के धौज का रहने वाला शोएब इस मामले में गिरफ्तार होने वाला सातवां आरोपी है।

- एनआईए ने फरीदाबाद में रहने वाले शोएब को हिरासत में लिया।

एनआईए की जांच से पता चला है कि शोएब ने 10 नवंबर को कार बम धमाका होने से पहले उमर को रसद सहायता प्रदान की थी। इस धमाके में कई लोग मारे गये थे तथा कई अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने जांच के तहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप की लाज बचाने के लिए जरुरी है कि राष्ट्रपति ज़ैलेन्स्की वॉशिंगटन जाएं, शांति प्रस्ताव पर बातचीत करने

अन्यथा, ट्रंप की प्रतिष्ठा यह ही बनकर रह जाएगी कि वे बड़ी-बड़ी डींग मारते हैं, पर उनके बड़-बोलेपन का जमीन पर कुछ असर नहीं होता

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति के रुप में अपने कार्यकाल अवधि के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक हालात लगातार उनके खिलाफ होते देख रहे हैं और जनता का विश्वास भी रिकॉर्ड स्तर तक गिरा है। हाल के हफ्तों में आए राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में यह साफ दिखा कि लोग उनकी कामकाज की शैली से असंतुष्ट हो रहे हैं। घरेलू तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और नीतियों को लेकर अस्पष्ट संदेशों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ट्रम्प, जो हमेशा राजनीति के नियमों को धता बताने पर गर्व करते थे, उनके लिए ये आंकड़े एक गंभीर चेतावनी हैं। फिर भी, इन मुश्किलों के बीच यूक्रेन-रूस शांति समझौते की दिशा में उनका बड़ा और सक्रिय प्रयास एक संभावित पोलिटिकल लाइफलाइन के रूप में उभरा है, ऐसा कदम, जो सफल होने पर देश और विदेश, दोनों जगह उनकी स्थिति मजबूत कर सकता है।

नवीनतम सर्वे के पैटर्न साफ दिखाते हैं कि अलग-अलग वर्गों में उनके समर्थन में गिरावट आ रही है। रिपब्लिकन रुझान वाले स्वतंत्र मतदाताओं का समर्थन भी कमज़ोर पड़ रहा है और उदारवादी वर्ग में उन पर संदेह बढ़ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भले ही उनका पक्का वोटर वर्ग अभी भी उनके साथ है, लेकिन वह व्यापक समर्थन, जिसने उन्हें दोबारा सत्ता तक पहुंचाया था, अब अस्थिर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति के रूप में आंतरिक अस्थिरता की छवि उनके उस दावे को ढँकने लगी है, जिसमें वे खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत नेता बताते रहे हैं।

- यह छवि, उनकी सरकार को ले डूबने के लिए काफी है।
- अतः, उनकी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि ज़ैलेन्स्की वॉशिंगटन जरुर आएं, अन्ततोगत्वा कोई "डील" (समझौता) हो या न हो, यूक्रेन-रूस युद्ध में।
- ट्रंप के लिए यह भी जरूरी है कि रूस भी शांति प्रस्ताव पर झूठी सच्ची "हामी" भरे। अतः ट्रंप भारी रूप से चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि ट्रंप के वफादार समर्थकों के अलावा, छोटी-मोटी पार्टी वाले समर्थक, जो उनको सत्ता में बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, भी धीरे-धीरे खिसक रहे हैं।

इस स्थिति में, पूर्वी यूरोप में शांति के प्रयासों में अचानक आई तेजी का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। खबरें हैं कि यूक्रेन ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा कराए जा रहे शांति समझौते को "मूल रूप से स्वीकार" कर लिया है, भले ही अभी सहमति पक्की नहीं हुई हो, लेकिन यह वाइट हाउस को राष्ट्रीय चर्चा को नया रुप देने का मौका देती है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने सी.बी.एस. न्यूज को बताया कि कीव ने अमेरिकी ढांचे के मुख्य बिंदुओं को मान लिया है और कुछ "छोटी बातें" तय होना बाकी हैं। अगर दुनिया के सबसे जटिल और लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों में अमेरिका कोई ठोस प्रगति कराता है, तो ट्रम्प खुद को एक बड़े राजनयिक नेता के रूप में पेश कर सकते हैं, खासकर ऐसे समय में, जब उनकी घरेलू छवि कमज़ोर पड़ रही है।

ट्रम्प के सलाहकार इस बात को भली-भांति समझते हैं। एक सफल शांति समझौता, या कम से कम उसकी दिशा में मजबूत प्रगति, गिरते पोल नंबरों का मुकाबला कर सकती है। इससे उनके उस लंबे समय से किए जा रहे दावे को भी बल मिलेगा कि एक वही हैं, जो ऐसी "डील" "करा सकते हैं," जो औरों से नहीं हो पाए। रिपब्लिकन पार्टी में उनके समर्थक अभी से ही उनकी सक्रिय कूटनीति की तुलना पिछली सरकारों की कथित रुकावट से कर रहे हैं। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की इस महीने अमेरिका आते हैं और समझौते को आधिकारिक रूप देते हैं, तो सिर्फ इससे बनने वाली छवि से ही वाइट हाउस को एक दुर्लभ राजनीतिक जीत मिल सकती है।

लेकिन यह प्रयास बेहद जटिल भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय संविधान का 9 भाषाओं में अनुवाद जारी किया

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह वह ऐतिहासिक दिन है, जब साल 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसके कुछ अनुछेद 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे। हालाकि, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, जिसके बाद भारत एक गणराज्य बना। इस साल 2025 में 76वें संविधान दिवस को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है।

- इससे देश के नागरिकों को अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने व समझने का मौका मिलेगा।

सरकार द्वारा इस साल संविधान के नौ भारतीय भाषाओं में अनुवाद जारी किये गये। यह पहल देश के नागरिकों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)